

प्रषक

मनीषा पंदार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 15 जनवरी, 2009

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या-5/45/2008-PP(PPR) दिनांक 11 दिसंबर, 2008 (छायाप्रति संलग्न), के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु वर्ष 2008-09 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र सहायित) दिये जाने हेतु रू० 1,81,291/- (रुपये एक लाख इक्यासी हजार दो सौ इक्यान्वे मात्र) की धनराशि राज्य के 36 छात्रों हेतु अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-434/XVII-3/2008-07(65)/2007 दिनांक 31.07.2008 द्वारा रू० 6,06,747.00 (रू० छः लाख छः हजार सात सौ सैंतालीस मात्र) तथा 02/xvii-3/2008-07 (65)/2007 दिनांक 01 जनवरी, 2009 द्वारा रुपये 32,500.00 (रुपये बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उक्त धनराशि पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के "आयोजनागत" पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से उपरोक्त प्रस्तर-01 में उल्लिखित रू० 1,81,291.00 (रुपये एक लाख इक्यासी हजार दो सौ इक्यान्वे मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-267/xxvii(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 के क्रम निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनद्व मर्दों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण / व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (ii) उक्त आवंटित धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्त हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
- (iii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) के आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (iv) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकरिमक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 "आयोजनागत" शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
- (v) वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
- (vi) मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अवचनवद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति कराना सुनिश्चित करें।
- (vii) यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (viii) अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (ix) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
- (x) बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं-0102-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति(100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) के मानक मद 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-624(P)/XXVII(3)08-09 दिनांक 07 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीया,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- 11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- उपसचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5/45, 2008- PP(PPR) दिनांक 11.12.08 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 13- बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन नि०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 16- आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनीषा पवार)
सचिव।